भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 429
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्ययन अवसंरचना का संपोषणीय आधुनिकीकरण

429 कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री गोडम नागेश :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री नव चरण माझी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री राजकुमार चाहर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ईको-फिशिंग पोर्ट्स, स्मार्ट हार्बर्स और ब्लू पोर्ट्स जैसी पहलों के अंतर्गत मत्स्यपालन अवसंरचना को आधुनिक, हरित और विस्तारित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;
(ख) क्या सरकार द्वारा मछली पकड़ने के हार्बरों में पर्यावरणीय स्थिरता, डिजिटल तकनीकों और जलवायु लचीलापन को एकीकृत करने के लिए कोई लक्षित हस्तक्षेप किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्षमता निर्माण और वित्तपोषण के लिए एजेंस फ्रांसेज़ डे डेवेलपमेंट (फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी) जैसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थायी (सस्टेनेबल) और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) नामक एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के इको-फिशिंग पोर्ट्स और ब्लू पोर्ट पहल पर आधारित स्मार्ट और ग्रीन कंपोनेन्ट्स के साथ फिशिंग हार्बर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, आधुनिकीकरण और विस्तार, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना(PMMSY) के तहत परिकल्पित और सहायता प्रदत्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

(ख): सरकार द्वारा फिशिंग हार्बर में पर्यावरणीय स्थिरता, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और जलवायु परिवर्तनों को मजबूती से सामना करने (क्लाईमेट रेसीलिएन्स) के आयामों को एकीकृत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप किए गए हैं और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 369.8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के साथ क्रमशः दीव में वनकबारा, पुदुच्चेरी में कराईकल और गुजरात में जखाऊ में तीन स्मार्ट और इन्टीग्रेटेड फिशिंग हार्बर को स्वीकृति दी है। भारत में स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर का विकास, पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी, दक्षता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिशिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए एक इन्नोवेटिव अप्रोच को उजागर करता है। फिशिंग हार्बर में स्मार्ट तकनीकों का कार्यान्वयन, संचालन में सुधार, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और स्थायी (सस्टेनेबल) पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार की फिशरीस इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं केंद्र और संबंधित राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में लागत साझाकरण के आधार पर शुरू की जाती हैं। स्मार्ट और इन्टीग्रेटेड फिशिंग हार्बर परियोजना के महत्वपूर्ण घटक हैं:- (i) स्मार्ट टेक्नोलॉजी (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन नीलामी सुविधा, पोर्ट वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स , IoT डिवाइस, सेंसर कम्युनिकेशन नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा मेनेजमेंट सिस्टम, विश्लेषण, विज़ुअलाइज़ेशन आदि) (ii) कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी (इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेटेलाइट कम्युनिकेशन संचार प्रणाली, वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्किंग उपकरण और साइबर सुरक्षा उपाय) (iii) सुरक्षा उपकरण (iv) संरक्षण उपाय (v) नेविगेशनल और रेडियो-संचार उपकरण (vi) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जैसे सौर ऊर्जा आदि (vii) रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम (viii) ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटिंग सिस्टम (ix) अपशिष्ट प्रसंस्करण उपकरण (x) फिश हैंडलिंग (ट्राइपॉड, कन्वेयर) (xi) ईटीपी (xii) ओटोमेटेड़ सिस्टम्स (क्रेन, बर्फ ढोने के लिए कन्वेयर) (xiii) ग्रीनरी और लैंडस्केपिंग आदि।

(ग) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2025 में भारत में ब्लू पोर्ट्स को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम [टेक्निकल कोओपरेशन प्रोग्राम (TCP) के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने फ्रेंच डेवलेपमेंट बैंक (AFD) के सहयोग से मई, 2025 में इको-फिशिंग पोर्ट की अवधारणा पर कार्यशाला आयोजित की है। इसके अलावा, विभाग मात्स्यिकी क्षेत्र को संगठित बनाने और मात्स्यिकी से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना "प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सेह योजना (PM-MKSSY)" का कार्यान्वयन कर रहा है। PM–MKSSY एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है, जिसमें वर्ल्ड बैंक (1125 करोड़ रुपए) और AFD (375 करोड़ रुपये) से ऋण के रूप में 1500 करोड़ रुपए शामिल हैं।

******